Mr. Deputy-Speaker: The result of the division is:

Ayes*	38
Noes	108

The motion is lost.

The motion was negatived.

Some hon. Members: Shame, shame.

17.37 hrs.

INSTITUTE OF INTERNATIONAL STUDIES†

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kishen Pattnayak.

Shri S. Kandappan (Tiruchengode): Sir, I rise on a point of order. This half-an-hour discussion pertaining to the Institute of International Studies is being taken up in this House for the third time. It is a deliberate attempt to malign an institute of international repute for the simple reason that that institution has not accommodated some fanatic Hindi elements within the campus of that institution. The fact that a centrally sponsored university or an institution deemed to be a centrally sponsored one, simply because it is centrally sponsored....

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

Shri S. Kandappan: I am coming to it. This is the first time I am raising a point of order in this House after I entered this House.

Mr. Deputy-Speaker: What is the rule or article that has been infringed?

Shri S. Kandappan: Simply because it is a central institution it does not mean that the institution should give only scope for Hindi. The accident of the situation of the institution in some Hindi area....

Mr. Deputy-Speaker: You are arguing on merits.

Shri S. Kandappan: It is a question of academic freedom. It is a reputed institution which is serving the whole of India and not only my Hindi friends here. It is an institution for all of us. If they mean to denigrate or suppress an institution of its autonomy, it is not fair.

Mr. Deputy-Speaker: You have not shown me how there is any point of order arising. You have been speaking for the last five minutes.

Shri S. Kandappan: The dignity and decorum of this House demand that this kind of repeated attempt on the part of some Hindi imperialists just to have Hindi everywhere to the degradation.....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order; there is no point of order. Shri Kishen Pattnayak.

Shri S. Kandappan: I pray that this should not be allowed to be taken up in this House.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Under what rule are you raising the point of order?

Shri S. Kandappan: Government has decided its policy. How can they bring it in the House repeatedly? *(Interruption)*

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. There is no point of order.

श्री चन्द्र मणिलाल चौधरी (महुआ): हिन्दी आपकी जबान नहीं है तो अंग्रेजी भी नहीं है।

Shri S. Kandappan: Let my Hindi friends appreciate one point that when we use English in this House, it is not that English is our mother-tongue but it is in the larger interest of the national unity. We are graceful enough to tolerate proceedings in Hindi in the House. At least courtesy should be shown to us.

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of orders. Shri Kishen Pattnayak.

---

*Shri M. R. Masani, Shri Surendranath Dwivedi and Dr. Saradish Roy also wanted to vote for "AYES".

†Half-An-Hour Discussion.

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : मैं कण्डप्पन साहब से कहना चाहता हूं मेरी अपनी मातृ-भाषा भी हिन्दी नहीं है ।

श्री मधु लिमये : यहां तामिल चले, मैं सौ फी सदी आपके साथ हूं ।

Shri S. Kandappan: Is there a provision in the rules for me to speak in Tamil?

श्री मधु लिमये : आप तमिल में बोलिये मैं आपका साथ दूंगा ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Please sit down.

Shri S. Kandappan: When I tried to speak in Tamil, I was not allowed. It was on record.

श्री किशन पटनायक : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी में बहुत सी तिकड़मी संस्थायें हैं जिनको सरदार कपूर सिंह ने रैकेट कहा था । जहां तक स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज की बात है, मंत्री महोदय कभी कभी खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की संस्था है । क्यों ऐसा कहते हैं—उसका कोई कारण कभी नहीं बताया । जहां तक मैं जानता हूं, श्री चागला साहब ने पिछली बार इस के लिये कहा था कि इस संस्था की एक विशेषता यह है कि इस में एरियाज की स्टडी होती है, स्पेशलाइजेशन होता है, क्या स्पेशलाइजेशन होता है, वह मैं ने पिछली बार भी बताया था और आज फिर से दोहरा देता हूं । इस इंस्टीचूट में एक अध्यापक हैं जिन्होंने नेपाल पर काम किया है लेकिन उन को दिया गया है कामनवेल्थ का डिपार्टमेंट, एक दूसरे अध्यापक जिसने यू० एन० ओ० पर काम किया है उन को भी कामनवेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ में रखा गया है और जिस ने अफरीका कांगों पर काम किया है उसको सेन्ट्रल एशिया दिया गया है । यह आपकी एरिया-स्टडीज का स्पेशलाइजेशन है ।

इस के साथ कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिन में कोई स्टडीज ही नहीं हुई हैं, 10 साल में एक भी शोध ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है, जैसे कि सेन्ट्रल एशिया का डिपार्टमेंट है । इस के अतिरिक्त जितनी किताबें अभी तक प्रकाशित हुई हैं और ग्रन्थ बने हैं उनकी कोई बिक्री नहीं हुई है । किताबें छपा दी जाती हैं, लेकिन बिकती नहीं हैं, इंस्टीचूट के गोदाम में पड़ी हुई हैं और जब भी उस में से किसी का रिव्यू होता है तो उसको "ट्रेश" कहा जाता है । इस तरह का काम इंस्टीचूट कर रहा है और पैसे की फजूलखर्ची तो वहां बहुत ही ज्यादा है ।

17.45 hrs.

[SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

मैंने बताया था कि इस इंस्टीचूट में एक विद्यार्थी पर 10 हजार खर्च होते हैं जब कि अन्य यूनिवर्सिटियों में बहुत कम खर्च होता है, लेकिन यहां पर इतना रुपया पढ़ाई पर खर्च नहीं होता है इस में ज्यादातर खर्च होता है क्लर्कों पर, अध्यापकों और स्टाफ पर और मकानों पर । सन् 1965–66 में इस इंस्टीचूट में क्लैरिकल स्टाफ पर एक लाख 51 हजार रुपये खर्च हुए, टीचिंग स्टाफ पर 2 लाख 60 हजार रुपये खर्च हुए, जब कि विद्यार्थियों पर केवल 65 हजार रुपये खर्च हुए । इस के साथ ही यहां एक मकान का इन्आगूरेशन हुआ था उस में यू० जी० सी० ने 500 रुपया ग्रान्ट दी थी लेकिन इस इंस्टीचूट ने उस पर 6 हजार रुपये खर्च किए । इस किस्म की फिजूलखर्ची इस रैकेट में होती है ।

अब जहां तक आज का जो मुख्य विषय है—हिन्दी में शोध-पत्र लिखने की इजाजत, उस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उस दिन छागला साहब ने एक रेजोल्यूशन हमारे सामने रखा था । इस इंस्टीचूट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, जो कि बहुत मूर्खतापूर्ण है । उस रेजोल्यूशन को बता कर छागला साहब कुछ आश्वासन देना चाहते थे कि हिन्दी को भी और अन्य भारतीय भाषाओं को वहां स्थान मिलेगा । लेकिन मैं उन को बता देना चाहता हूं कि हाल में उस विद्यार्थी के लिये वार्षिक परीक्षा का अवसर आया और उसने अपना शोधपत्र सबमिट किया अपने डिपार्टमेन्ट के हेड के सामने, जो उसने

हिन्दी में लिखा था। लेकिन चूंकि यह हिन्दी में लिखा था, इसलिये उस को लौटा दिया गया, नामन्जूर कर दिया गया, उस पर कोई जांच भी नहीं हुई। यहां पर मैं छागला साहब को बता देना चाहता हूं कि यह कौन सा डिपार्टमेन्ट था ? यह ऐसा डिपार्टमेन्ट है कि जिस में अभी तक एक भी थीसिस नहीं आया है और इस बेचारे विद्यार्थी ने इस डिपार्टमेन्ट पर एक थीसिस लिखने की कोशिश की—यह डिपार्टमेन्ट है सेन्ट्रल एशिया का डिपार्टमेन्ट। सेन्ट्रल एशिया के बारे में मैं छागला साहब को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि सेन्ट्रल एशिया पर अंग्रेजी में किताबें बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि उस से कहीं ज्यादा ग्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं, हो सकता है कि रूसी भाषा में भी ज्यादा ग्रन्थ हों, लेकिन सेन्ट्रल एशिया के बारे में अंग्रेजी में कम किताबें हैं, हिन्दी में ज्यादा किताबें हैं। इस सत्य को छागला साहब न भुलायें। अब यह जो रेजोल्यूशन हुआ है, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, इस में कहा गया है—कब इजाजत दी जायगी भारतीय भाषा को, जब उस भाषा में पर्याप्त पढ़ने की सामग्री मिल जायगी और जब ऐसे अध्यापक होंगे और जांच करने वाले होंगे जिनको उस भारतीय भाषा की जानकारी होगी। यह इतना मूर्खतापूर्ण है कि एक तरफ़ तो कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों में मीडियम भारतीय भाषायें इसलिये नहीं बनती हैं कि भारतीय भाषाओं में किताबें नहीं हैं, भारतीय भाषाओं में शोध ग्रन्थ नहीं हैं, भारतीय भाषाओं में अभी कुछ कार्य नहीं हुआ है, इसलिये विश्वविद्यालयों या स्कूलों में माध्यम भारतीय भाषायें होनी चाहियें, लेकिन दूसरी तरफ़ जब एक विद्यार्थी कोशिश करता है कि भारतीय भाषा में ग्रन्थ लिखे और खुद जोखिम उठा कर जब ऐसा प्रयत्न करता है, तब आप उस को इजाजत नहीं देते हैं।

जहां तक किताबों की बात है कि भारतीय भाषाओं में किताबें नहीं मिलती हैं, इस का जवाब मैं खुद न दे कर श्री रविन्द्र नाथ टैगोर से जवाब दिलाऊंगा। मैं श्री छागला साहब से इतना निवेदन करूंगा कि छागला साहब या कोठारी साहब अपने को बहुत बड़ा शिक्षाविद न मानें और जरा ख्याल करें कि हिन्दुस्तान में शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में और कोई सचमुच में मनिषि हमारे देश में हाल के समय में हुए हैं तो वे थे—महात्मा गांधी और दूसरे थे—श्री रविन्द्र नाथ टैगोर। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो लिखा है वह मैं यहां पर पढ़ कर सुनाता हूं, खास तौर से जब यह कहा जाता है कि किताबें नहीं हैं, इसलिये माध्यम भारतीय भाषायें कैसे बन सकती हैं—

> "I know what the counter-argument will be. 'You want to give higher education through Indian languages, but where are the text-books? I am aware that there are none. But unless the higher education is given in our own languages, how are the text-books to come into existence?"

आप अगर शोध ग्रन्थ नहीं लिखने देंगे तो किताबें बनेंगी कैसे ? माध्यम होगा कब ? इस आर्गूमेन्ट का तर्क छागला साहब याद कर लें।

दूसरी बात यह है कि जहां जो विकसित भाषा है जैसे जर्मनी में जर्मन भाषा है, तो जो लोग जर्मन भाषा में शोध ग्रन्थ लिखते हैं उन को पढ़ने की सामग्री जर्मन भाषा में नहीं मिलती है, उनको पढ़ने की सामग्री दूसरी भाषाओं में मिलती है। जैसे उस दिन डा० लोहिया ने कहा था कि मैक्स म्यूलर ने कई ग्रन्थ लिखे, बहुत बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे, लेकिन उन ग्रन्थों को लिखने के लिये पढ़ने की सामग्री उन को संस्कृत भाषा में मिली। पढ़ने की सामग्री जिस भाषा में मिलती है यह जरूरी नहीं है कि शोध ग्रन्थ भी उसी मीडियम में लिखा जाय। यह बात समझ लेनी चाहिये, हमारे यहां इतने शिक्षाविद हिन्दुस्तान में हैं। इस के साथ कांस्टिट्यूशन

[श्री किशन पटनायक]

का 351 अनुच्छेद है जो कहता है कि हिन्दी को एक समृद्ध भाषा बनाने, एक समृद्ध अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है । इस को श्री चागला काट कर अपने दफ्तर में लटकायें आंखों के सामने ताकि भूल न जायें क्योंकि जो जिम्मेदारी आप के ऊपर है उस को आप निभायेंगे कैसे । जिस संस्था को आप इतने पैसे देते हैं, शत प्रतिशत अनुदान देते हैं, अगर उस संस्था के जरिये आप संविधान के इस अनुच्छेद को कार्यान्वित नहीं करेंगे तो किस संस्था के जरिये करेंगे । संविधान का अनुच्छेद 351 आप को मजबूर कर देता है और आज समय की मांग है कि आप इस को मान लें ।

Shri S. Kandappan: The best thing would be to scrap that article.

श्री किशन पटनायक : जहां तक अध्यापकों की बात है, जिस विद्यार्थी के सम्बन्ध में बहस शुरू हुई उस विद्यार्थी का जो प्रोफेसर है वह बिल्कुल हिन्दी जानने वाला है । अंग्रेजी तो खैर, जहां तक मैं जानता हूं, उसे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती है, लेकिन हिन्दी जरूर उस को मालूम है, और अगर उस को हिन्दी न भी मालूम हो, तो 351 अनुच्छेद के अनुसार यह आप का कर्त्तव्य है कि आप उस को प्रोत्साहन दें । विद्यार्थियों को अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में, हिन्दी भाषा में, गुजराती भाषा में, दूसरी भाषाओं में कार्य करने के लिये जितनी सहूलियतें चाहियें उन को दिलाना सरकार का धर्म और कर्त्तव्य हो जाता है ।

जब से यह वैदिक का सवाल उठा, दूसरे इन्स्टिट्यूट्स और दूसरे विद्यार्थियों के मन के अन्दर यह आशा पैदा हो गई है कि शायद गवर्नमेंट उन लोगों को भी अपने कामों की थीसिस अपनी भाषा में लिखने का मौका दिला दे, और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट भी कर दी है । जैसे कि गुजरात की एक विद्यार्थिनी ने कह दिया है कि वह भी चाहती है कि गुजराती भाषा में अपने कामों की थीसिस लिखे । इसी तरह से लोग तमिल में लिखना चाहते हैं । जब आप एक बार यह बात शुरू कर देंगे, कोई रोक नहीं लगायेंगे, और विद्यार्थियों को मालूम हो जायेगा कि अगर वे अपनी भाषा में अपने शोध कार्य को लिखना चाहेंगे तो उन को जरूरी सहूलियतें मिल जायेंगी, प्रोफेसर भी मिल जायेंगे, सारी सुविधायें हो जायेंगी तब फिर इस बात की एक बाढ सी आ जायेगी और शोध ग्रन्थ ज्यादातर अपनी भाषा में, भारतीय भाषाओं में लिखे जाने लगेंगे । जब शोध ग्रन्थ भारतीय भाषाओं में लिखे जाने लगेंगे तब आप ने जो दस साल का फैसला किया है वह गलत है क्योंकि दस साल तो बहुत दूर हैं, तत्काल यह हो जाना चाहिये कि विश्वविद्यालय का माध्यम भारतीय भाषायें होनी चाहियें, आंचलिक भाषायें होनी चाहियें । आप अगर अभी से शोध ग्रन्थ भारतीय भाषाओं में नहीं लिखवाते हैं तब आप दस साल तक भी कैसे विश्वविद्यालय का माध्यम भारतीय भाषाओं को बना सकते हैं । क्या आकाश से किताबें लायेंगे या सड़क से लायेंगे या पाकिस्तान से लायेंगे, चीन से लायेंगे ।

आखीर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत के शिक्षा मंत्री तीन प्रकार के हो सकते हैं । एक तो वह हो सकता है जो अपनी नीति अपने देश के आधार पर या एक महान शक्तिशाली राष्ट्र के आधार पर बनाये, दूसरे ऐसा शिक्षा मंत्री भी हो सकता है जो शिक्षा के बारे में कुछ न जानता हो और कुछ कर न सकता हो । तीसरे ऐसा शिक्षा मंत्री हो सकता है जो कि जाने या अनजाने पाकिस्तान या चीन की दलाली का काम करे और इस तरह से अपनी नीति बनाये जिस से देश भी टूटे, भाषा भी टूटे और यह देश बिल्कुल विकसित न हो सके ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस संस्थ का 30 लाख या इस से अधिक रुपया हिमालय के ऊपर शोध कार्य के लिये अब तक खर्च हुआ, और उस का समय अक्तूबर में बीतने वाला है ।

एक माननीय सदस्य : बीत चुका है ।

श्री रामसेवक यादव : समय बीत चका है, लेकिन इस के सम्बन्ध में एक अक्षर भी काम नहीं हुआ है । दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संस्था ने एक भी शोध कार्य इस तरह का किया है जिस का नाम देश और विदेशी स्तर पर हो । अगर किया है तो जरा उस का नाम भी बतला दें ।

Shri Umanath (Pudukkottai): If I have understood the position taken by Shri M. C. Chagla on the question of allowing thesis in the respective Indian languages, he has stated that the institute will permit the writing of thesis in the various Indian languages provided two conditions are satisfied. And it is on those two provisos that I want to ask a question. The first is adequate material in the language being available; second, competent supervisors and examiners being available. I think this Institute has been there for the past ten years. I would like to know whether any investigation was undertaken by the Institute to find out if adequate materials in various Indian languages are available and also whether competent supervisors and examiners are available. If so, what was the result? If not, what steps have Government taken to bring about a situation in these two directions?

Shri Sezhiyan: Are Government aware of the growing apprehension in the minds of the non-Hindi people that all the Institutions of higher education and research of an all-India character happen to be situated in Hindi-speaking areas, due to which there is an increasing pressure and coercion to make these institutions of all-India character just Hindi institutes, and that being so, there is need to establish institutes of higher education and research with the same facilities and central assistance in the non-Hindi areas, especially in the south, so that they could go on with that and keep up the same standard of work without linguistic fanaticism from outside?

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon): In view of the fact that this Institute is carrying on post-graduate and research studies, in view also of the fact that there must be some uniform standard for students as well as teachers, and in view further of the fact that there is scarcity of teachers knowing Hindi and examiners knowing Hindi and also of books in Hindi on the various subjects handled by the Institute, may I know whether it is the policy of Government to surrender to the pressures exerted by the Hindi fanatics and imperialists and allow the standard of universities education to be lowered so that we become a laughing stock in the world in matters of international importance?

Shri Rajaram (Krishnagiri): I want to know whether because the Institute of International Studies happens to be located at Delhi, Government are thinking of introducing Hindi inside the Institute, removing any chance for other regional languages like Tamil, Gujarati, Malayalam and others. I was told that there was no teacher or professor in the Institute to teach in other languages like the ones I have mentioned and that this Institute has no research study so far undertaken in any other language. I want to know from Government whether they are going to maintain any standard in consonance with the standard of education in foreign universities.

Shri S. Kandappan: We are interested in upholding the standard of our educational institutions, particularly post-graduate and research institutions. Now that Hindi imperialism is on the rampage to destroy everything in its way, are Government prepared to suitably amend the Constitution so that they do not give a weapon, a handle, to the fanatics of Hindi to destroy everything in their way, so that we uphold and safeguard the academic freedom of our higher educational institutions?

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): In view of the fact that the very name of the Institute shows that it is intended for international studies, may I know whether Government will see that the language controversy and fanaticism will not be brought into this Institute so that the Institute is not spoiled and the opportunity available to all students from all language groups in India to do research and post-graduate studies is not denied?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को क्या यह बात मालूम है कि भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि संविधान की चौदह भाषाओं को संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाये । यदि वह बात मालूम है तो इस के अनुरूप भारत सरकार ने शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन किया है और क्या इस इन्स्टिट्यूट के अधिकारियों को भी यह बात बतलाई गई है कि इस के अनुरूप इस इन्स्टिट्यूट की नीति में परिवर्तन किया जायेगा । यदि हां तो उस इन्स्टीट्यूट ने इसके मुताबिक अब तक क्या कोई परिवर्तन किया है ?

18 hrs.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था इसलिये मानते हैं कि इस संस्था ने जहां पर शिक्षण और शोध कार्य में कुछ हजार रुपया खर्च किया है वहां लाखों लाख रुपये का अपव्यय किया है ? क्या वह इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था इसलिये मानते हैं कि इस संस्था ने वहाली का और लोगों को निकालने का कोई नियम नहीं बनाया है ? क्या इसलिए वह इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था मानते हैं कि सेंट्रल एशियाटिक डिपार्टमेंट में दस वर्ष के बाद भी आज तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ है ? क्या वह इस को अन्तर्राष्ट्रीय संस्था इसलिए मानते हैं.....

सभापति महोदय : एक सवाल ही आप पूछ सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में, संसद में, तथा जनता में कामनवैल्थ के खिलाफ जब प्रचार हो रहा था उस समय इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कामनवैल्थ की स्पोर्ट में लम्बे लम्बे आर्टिकल लिख रहे थे, इस वास्ते क्या इसको वह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था मानते हैं ? और क्या यह जो मैं कह रहा हूं बात सच नहीं है ? चेयरमैन साहब मैं चेलेंज करता हूं और मैं नाम भी दे सकता हूं कि इस संस्था में जो विद्यार्थी रिसर्च के नाम पर आए, वे कल आए और आज रीडर बन गए, क्या यह भी सच नहीं है ? क्या यह भी सच नहीं है कि एक श्री के० आर० सिंह नाम के विद्यार्थी ने सम्पूर्ण संसार घूमा और उन्होंने हजारों डालर इंस्टीट्यूट का खर्च किया लेकिन आज तक अपनी रिसर्च का मोनोग्राम तक नहीं लिखा ? क्या इसको अन्तर्राष्ट्रीय संस्था इसलिए नहीं कहा जाता है कि डा० कुंजरू की सिफारिश पर हिमालयन प्राजेक्ट नाम की एक प्रोजेक्ट ली गई थी तीन वर्ष पहले और उस हिमालयन प्राजेक्ट पर बहुत सा रुपया खर्च भी हो गया लेकिन अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ...

Shri Nambiar: We also know how to make speeches. We did not do that. We only put a question. This is wrong.

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । सभापति महोदय, इन्होंने प्रश्न किया तो मैंने इनको बिल्कुल नहीं टोका । हमें ये हिन्दी इम्पीरियलिस्ट्स के नाम से पुकारते हैं, हमें ये गालियां देते हैं, बार बार गालियां बकते हैं.....

Shri Nambiar: You are making a speech.

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं समाप्त कर रहा हूं । क्या ये सारी बातें सच नहीं हैं

कि इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के नाम पर रुपये का अपव्यय, बहाली आदि में नेपोटिज्म, ब्राइबरी करप्शन आदि होते हैं और क्या यह बात भी सच नहीं है कि डा० कुंजरू की सिफारिश पर हिमालयन प्राजैक्ट के नाम पर हजारों रुपया तो इसने खर्च कर दिया है लेकिन अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सारी बातें झूठ हैं ?

Shri Basappa (Tiptur): May I know whether the various State Governments have awarded any scholarships to be given to the students, if so, how many scholarships have been instituted by various State Governments in this institution and how many students are being benefited by that? What is the number of students who are studying in this institution, and supposing the theses have to be written in all the languages; how many language teachers are needed and what will be the total expenditure for this institution, how much of it is given by the Government?

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मैंने नाम दिया था ।

सभापति महोदय : मेरे पास तो आपका नाम नहीं है ।

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): I think it is most unfortunate that remarks should have been made running down an institute of very high standing in our country and also in the world outside. We have heard a great deal in this House of character assassination. That was restricted to personalities. I am sorry that my hon. friend Shri Azad has now started character assassination with regard to the institution.

Shri Bhagwat Jha Azad: I strongly oppose Mr. Chagla. You are trying to assassinate my character. Please stop this, I tell you. Do not talk in that way, I tell you. You are assassinating my character. You are trying to do that. (*Interruptions*)

Shri M. C. Chagla: I have got his words here. He has talked of bribery and corruption in this institution.

Shri Bhagwat Jha Azad: Please talk like a Minister. Do not try to abuse. (*Interruptions*).

श्री रामसेवक यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें और उनको बिठा दें ।

Shri Bhagwat Jha Azad: You are trying to put one against another. Please talk about the institution.

Shri M. C. Chagla: I am talking about the institution.

Shri Bhagwat Jha Azad: He wants we should fight here (*Interruptions*).

श्री रामसेवक यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

Mr. Chairman: Which rule has been infringed?

श्री रामसेवक यादव : जो बहस चल रही है उस पर मैं उठा रहा हूं । मैं चरित्र हनन के बारे में कहना चाहता हूं । जब कभी कोई आरोप कहीं किसी गलती को ले कर उठाये जाते हैं तो चरित्र हनन की बात मंत्री महोदय कह दिया करते हैं । मैं चाहता हूं कि चरित्र हनन का प्रश्न इस तरह से मंत्री महोदय न उठाया करें ।

Mr. Chairman: The hon. Minister is perfectly right in using that expression.

Shri M. C. Chagla: If necessary Mr. Azad can look at the record; I have taken down his words. He said that there was bribery and corruption in this Institute. If that is not character assassination of an institute, I do not know what is.

Shri Bhagwat Jha Azad: Let these facts be read; they will show if I am wrong.

Shri Nambiar: Who gave those facts?

Shri Bhagwat Jha Azad: We will pass it on to you.

Shri Kishen Pattnayak: Have a judicial enquiry to see if there is not corruption... (*Interruption.*)

श्री पालीवाल (हिण्डौन) : किसी परसन के ऊपर परसनल अटैक हो तो चरित्र

[श्री पालीवाल]

हनन का प्रश्न उठ सकता है। लेकिन यहां पर तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंस्टीट्यूट की . .

Mr. Chairman: Mr. Paliwal, please resume your seat.

Shri N. Sreekantan Nair: The institute had already been named.

श्री पालीवाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है । कहां से यह करेक्टर एसेसीनेशन हो गया ?

Mr. Chairman: I am sorry you are obstructing the proceedings of the House. Mr. Paliwal. Please resume your seat.

Shri M. C. Chagla: I repeat: if you say that an institution is corrupt, there is corruption and bribery in an Institute, you are trying to ruin the reputation of that Institute.

Shri Ram Sewak Yadav: If there is corruption, why cannot a judicial enquiry be held? ..... (*Interruptions*).

Shri Bhagwat Jha Azad: We are prepared to see that through; I stand by the charges. I am prepared to give one dozen names.

Mr. Chairman: You had your turn; you had your say .... (*Interruptions.*)

Shri M. C. Chagla: If Mr. Azad will give me any instance of corruption or bribery, I assure him and this House that I will look into them .... (*Interruptions.*)

Shri Paliwal: If there is waste of public money, what is it?

Shri Bhagwat Jha Azad: Let there be a committee; I challenge; I will produce the facts.

Shri Nambiar: He has said that he is prepared.

Shri M. C. Chagla: I am prepared to look into them; I have already promised. We are not going .... (*Interruptions.*)

Shri Kishen Pattnayak: You have a committee of judicial enquiry.

Shri Nambiar: I have a point of order. the Minister is not allowed to reply ... (*Interruptions*). We want to hear him.

Mr. Chairman: There is absolutely no point of order.

Shri M. C. Chagla: This Institute, as I said, enjoys a very high status in our country; it enjoys a high status outside and it is not right that on the floor of this House we should make statements which will lower the prestige and dignity and status of that institution. I repeat again ....

Shri Ram Sewak Yadav: It is a racket.

Shri M. C. Chagla: It is character assassination.... (*Interruptions*).

Mr. Chairman: Order, order. You cannot go on like this.

Shri Ram Sewak Yadav: How can the Minister say that there is character assassination when there is an allegation.... (*Interruptions.*)

Shri M. C. Chagla: I repeat it is character assassination.

Shri Ram Sewak Yadav: I say Mr. Chagla you must learn that it is not character assassination.... (*Interruptions*).

Mr. Chairman: Order, order.

Shri M. C. Chagla: I am not going to be shouted down.

Shri Nambiar: We want to hear him.

Shri Ram Sewak Yadav: We see what you have done in Rajya Sabha; you have moved a privilege motion. Everywhere character assassination was the charge.

Mr. Chairman: I am so sorry, Mr. Yadav, you are obstructing the proceedings.

Shri Bhagwat Jha Azad: Reply to our charges, no generalisations.. (*Interruptions.*)

Mr. Chairman: Order, order. You must hear him.

Shri M. C. Chagla: If you do not want me to say so, do not use the word 'racket .... (*Interruptions*).

Shri Ram Sewak Yadav: Why not? If there is racket.... (*Interruptions*).

Shri M. C. Chagla: This Institute was inaugurated by no less a person than the President of India, who was then Vice President on 3rd October, 1955. One of the main objectives of the school was the advancement of knowledge of international affairs in India. The school is designed to be a centre for advanced studies in international affairs and a centre of studies with special reference to political, economic and social developments in the countries of Asia; it is for both Indian and foreign students. The school is the premier national centre for the training of post-graduate students in international affairs.

So, you must realise what is the nature of the institution. It is a post-graduate institution; it is not an under-graduate institution. It is intended to study international affairs; it is intended to study the developments. We want to strengthen our foreign service; the External Affairs Ministry sends officers for a short course and also a longer course. This institution teaches them in a particular subject with reference to where they are being posted. We have students from all over India. I gave the figures last time, and I am prepared to give them again. We have professors and teachers from all over India. We have professors from abroad; students from abroad have come to this institution. I can produce the certificates, testimonials given by people who have come from abroad and who have been tremendously impressed by the very fine research work that is being done in this school. That is why I feel so indignant when these remarks are being made about this institution.

Shri Bhagwat Jha Azad: It is all wrong.

Shri M. C. Chagla: What is all wrong?

Shri Bhagwat Jha Azad: We are charging you with definite instances; please speak on them. I always support the objective of the Institute of International Studies; please reply to those charges. Do not speak like this.

Shri M. C. Chagla: What are the charges? I have already told Shri Azad that if he can give me specific instances, I shall enquire into them. But now we have a general discussion on this institution, *(Interruption)*. First, about the medium of instruction. How is it possible today, when we get students from the South, when we get students from Bengal, when we get students from Maharashtra and other parts of the country who do not know Hindi, how is it possible....

Shri Ram Sewak Yadav: Why not have Marathi, why not have Bengali?

Shri M. C. Chagla: How many languages could we have?

Shri N. Sreekantan Nair: Let us have it in all the 14 languages.

Shri Basappa: Is it possible to have instruction in all the 14 languages? It is very difficult.... *(Interruption)*.

Shri Nambiar: Language studies will be done in elementary schools; not here.

Mr. Chairman: I request the Minister to conclude in two minutes. It is just an half-an-hour discussion.

Shri M. C. Chagla: Will you allow me five minutes? *(Interruption.)*

Shri Nambiar: It is not an elementary school for language study. It is for post graduate studies. Go ahead.

Shri M. C. Chagla: Teaching can be done only in one language; it is not possible to do in all the 14 languages here. Situated as we are, it must be done in English; it may be a foreign language, but in the context of the present situation, it cannot be helped.

As regards writing the thesis in Hindi, I have answered the question in this House that we will permit the thesis to be written in any Indian language provided we have a teacher or a guide who knows that language and who can teach the students or assist the students....

Shri Kishen Pattnayak: In this particulars case, he knows the language.

Shri Sheo Narain: Sir, there is no quorum in the House.

Shri N. Sreekantan Nair: Yes; let there be quorum. There is no quorum in the House.

Mr. Chairman: Order, order. Let us have quorum. The bell is ringing

Mr. Chairman: The bell has stopped ringing and there is no quorum. Under Direction No. 19 of Directions by the Speaker, the hon. Minister may, with the permission of the Speaker, lay a statement on the Table of the House later on.

Shri M. C. Chagla: If you permit me, I will lay a statement on the Table of the House on Monday or Tuesday.

Mr. Chairman: Yes; he may do so on Monday or Tuesday. As there is no quorum, the House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

18.18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, September 5, 1966/Bhadra 14, 1888 (Saka).

MGIPND—JOB II—1633 LS JC 10444—26-11-66